विचार बिन्दु

मनुष्य का कत्तर्व्य है कि वह उदार बनने से पहले त्यागी बने। -डिकेंस

ऐसी शिक्षा किस काम की?

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में सहायक हो, एक अच्छा नागरिक बनाए, एक तर्कशील, विवेकशील व्यक्ति का निर्माण करे और जो वैज्ञानिक सोच रखता हो। इस आलेख में यह विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन कसौटियों पर कितनी खरी उतरी है?

भारत की पहली शिक्षा नीति 1966 में, दूसरी 1986 में (जिसे 1992 में संशोधित किया गया) और हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति घोषित की गई। सभी नीतियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सबका उद्देश्य तो बहुत अच्छा था कि देश के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वह ऐसे नागरिक तैयार करे जिनमें वैज्ञानिक सोच हो एवं दक्ष नागरिक बनाएं एवं जो अपने जीवन यापन के पर्याप्त साधन जुटा सकें। साथ ही वे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सदैव उत्सक रहें।

सबसे पहले हम राजस्थान के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की ही बात करें। बालक बालिकाओं को अपनी स्थानीय बोली में पढाने के बजाय उन्हें हिंदी की पुस्तकों से पढाया जाता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। अनेक शब्द और व्याकरण भी अलग हैं। इस कारण छोटे बच्चों, विशेषकर ग्रामीण,को हिंदी में लिखी हुई पुस्तकें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। साथ ही पुस्तकों में काम लिए गए विभिन्न सन्दर्भों से भी उनका कोई जुड़ाव नहीं होता। इस कारण अनेक बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में ही शिक्षा चक्र से दूर हो जाते हैं। जो बच्चे औपचारिक विद्यालय में अनेक सामाजिक और आर्थिक कारणों से नहीं जा पाते, वे तो वैसे ही शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। उनके लिए अनौपचारिक शिक्षण की जो व्यवस्था थी, उसे भी सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार कानून' के नाम पर बंद कर दी है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने के सरकारी निर्णय ने तो कोढ में खाज का काम किया है। विभिन्न जटिलताओं के चलते स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की मान्यता प्राप्त करना वैसे ही संभव नहीं है।

स्कूली शिक्षा पद्धति में सबसे बडी खामी तो परीक्षा प्रणाली है जो केवल रटने पर आधारित है। समझ कर पढने का कोई महत्व नहीं है। पुस्तकों के अध्याय भी उनके संदर्भ से एकदम कटे हुए हैं। कई बार तो विदेशी संदर्भों का उपयोग किया गया है। पूरी मूल्यांकन प्रणाली कुंजियों से उत्तर रटने पर निर्भर हो गई है।

यही कारण है कि बोर्ड का 'पास' प्रतिशत इस बार 97-98-99% तक रहा है। अनेक विद्यार्थियों के 95%से अधिक अंक आए हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए केवल रटना होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा के तीन घंटे में रटा हुआ उत्तर सही उगल दे, वह लगभग पूरे अंक ले आता है। किसी विषय के बारे में समझ को जांचने का तो कोई प्रयास ही नहीं होता है। 90% प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों से उन्हीं के पाठ्यक्रम से संबंधित सरल प्रश्न भी यदि अलग तरह से पूछ लें, तो अधिकांश उन्हें हल नहीं कर पाते हैं। विभिन्न प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान इसीलिए खूब फलफूल रहे हैं और अभिभावक उनके आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं।

नौकरी प्राप्त करने के लिए भी वर्तमान परीक्षा पद्धति कुछ काम की नहीं है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहे तो पहले उसे स्नातक के बाद बी. एड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इसके लिए कोचिंग संस्थान हैं जो हज़ारों रुपए लेते हैं। इसमें उत्तीर्ण होने पर उसे दो वर्ष बी. एड की पढाई करनी होती है। इसकी फीस हजारों में है। इसके बाद उसे रीट (Rajasthan Eligibility Examination for teachers) की प्रतियोगी परीक्षा में बैठना होता है, जिसके लिए फिर कोचिंग करनी पड़ती है। इसमें सफल होने पर उसे फिर, रिक्तियां निकलने पर एक और चयन परीक्षा में बैठने होता है। इसके परिणाम के आधार पर मेरिट के अनुसार चयन होने पर शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाती है। जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन परीक्षा में आए हुए अंकों के आधार पर ही होगा तो शिक्षकों का भी पूरा ध्यान केवल इसी पर रहता है कि कैसे प्रश्नों के उत्तर रटा दिए जाएं ताकि वह परीक्षा में अधिक अंक हासिल कर सके।

यह दोष पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है कि बहुत अच्छे अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो वह बहुत अच्छा नहीं कर पाते।

जहां तक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का प्रश्न है, युवा पीढी के इतने वर्ष बर्बाद करने के बजाय, क्या यह अच्छा नहीं होता कि उन्हें स्नातक के परिणाम के आधार पर नौकरी पर रख लिया जाता? तत्पश्चात उन्हें नौकरी पर रहते हुए नियमित प्रशिक्षित किया जाता। इस प्रकार उन्हें अच्छा शिक्षक बनाया जा सकता है। इस प्रकार का अल्पकालिक प्रशिक्षण साल में दो तीन बार किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता केवल इसी बात की है कि वर्तमान में जो पढाई और मूल्यांकन की व्यवस्था स्नातक और 12वीं तक की है, उसे वैसा ही बना दिया जाए जिस प्रकार से चयन परीक्षा ली जाती है। इससे लाखों युवाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण कई वर्ष बर्बाद होने से बच पाएंगे। ऐसा करके हम, उन लोगों के द्वारा बी.एड और एस.टी.सी पर व्यर्थ हुए समय और धन को बचा पाएंगे जो अंततः शिक्षक नहीं बनकर किसी और व्यवसाय में लग जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग सफलता पूर्वक अन्य देशों में किए गए हैं।

हमारे यहां पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उच्च शिक्षा की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। सरकार, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से, प्रतिवर्ष कई नए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर देती है, किंतु पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षकों के अभाव में यहां पढाई मात्र की भी नहीं हो पाती। वैसे भी शिक्षकों के अभाव में किस प्रकार की पढाई हो सकती है, यह कल्पना ही की जा सकती है। राजस्थान में तीन दशक पूर्व जहां केवल तीन विश्विद्यालय थे, अब उनकी संख्या बढकर लगभग 100 हो गई है। कई निजी विश्विद्यालय तो युवाओं के आर्थिक और मानसिक शोषण का माध्यम बन कर रहे गए हैं। यहां तो पैसे लेकर डिग्री बेचने तक का कार्य होता है।

कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ना तो देश के किसी काम की है न विद्यार्थियों के। देश में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति और कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। अब देश प्रतीक्षा कर रहा है, शिक्षा क्रांति की। इस क्रांति के बाद ही भारत के विकास में, शिक्षा अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकेगी।

तकनीकी और मेडिकल के पाठ्यक्रमों की स्थिति और भी अधिक खराब है। जो इन पाठ्यक्रम में पढाया जाता है वह बाद में उनके जीवन में व्यवसाय को चलाने के लिए कतई उपयोगी नहीं होता। मुझे प्रबंध निदेशक, रीको के रूप में कार्य करते हुए कई बडे उद्यमियों द्वारा यह शिकायत की जाती थी कि इंजीनियरिंग स्नातकों में से 20 से 25% भी उनके यहां पर किसी काम को करने में सक्षम नहीं हैं। क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन अभिभावकों के साथ विश्वास घात नहीं है जो बडी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को कर्जा लेकर निजी विश्वविद्यालयों में पढने के लिए भेजते हैं? उच्च शिक्षा का तो यह हाल हो गया है कि कुछ वर्षों पूर्व, उत्तर प्रदेश में चपरासी के कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से कई तो पीएचडी और इंजीनियरिंग स्नातक तक भी थे।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा, युवाओं को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में असफल रही है।

जब से शिक्षा के निजीकरण पर सरकार ने बल देना प्रारंभ किया है, तब से ऐसा लगता है कि सरकार, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको प्रदान करने के अपने लक्ष्य से भटक गई है। इसमें बडी समस्या, शिक्षा के अंधाधुंध निजीकरण के कारण उत्पन्न हुई है जहां शिक्षा का पूरा क्षेत्र ही व्यवसाय बनकर रह गया है। लाखों रुपए वार्षिक शुल्क लेने के बाद भी महंगे निजी महाविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक कुछ भी काम करने के लिए उपयोगी नहीं बन पाते।

कहा जाता है कि निजी मेडिकल महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी अपना अस्पताल भले ही खोल लें, किंतु अस्पताल में इलाज करने की क्षमता उनमें विकसित नहीं हो पाती। शायद करोडों रुपए खर्च करके वे मेडिकल की पढाई भी अस्पतालों के मालिक बनने के लिए ही करते हैं ताकि व्यय किया गया पैसा शीघ्र वसूल कर सकें।

यह तो हुआ शिक्षा का एक पहलू, जिसके बाद उपयुक्त रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। अब यदि हम उनके अच्छे इंसान के रूप में और अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने की बात करें, तो इस दिशा में हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और भी असफल रही है। किसी भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा होती है कि वह सामाजिक सौहार्द को बढाने वाला, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला, जेंडर संवेदनशील और वैज्ञानिक सोच वाला होगा। क्या हम आज की युवा पीढी में इन गुणों का समावेश देखते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। हम देखते हैं कि आजकल के युवा अनेक समाज और राष्ट्र विरोधी आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो कर रह गए हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के कट्टर धार्मिक संगठन अपने-अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन्माद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इसीलिए संभव हो पता है कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का कोई व्यवस्थित प्रयास महाविद्यालयों में नहीं किया जाता। लगता तो ऐसा है कि, समय निकलने के साथ-साथ, अंधविश्वास, पूर्व की तुलना में कहीं अधिक बढता जा रहा है। यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश युवा तर्क हीन, विवेकशून्य और अंधविश्वासी हों, तो ऐसी शिक्षा वास्तव में न देश के लिए उपयोगी है, न उस व्यक्ति के लिए जो ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसमें दोष छात्रों का नहीं माना जा सकता। जिन व्यक्तियों के हाथ में शिक्षा का संचालन है, चाहे वे शिक्षाविद हों, शिक्षा प्रशासक हों अथवा जनप्रतिनिधि, सबका यह दायित्व है कि वे हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और उसे आज के समय की आवश्यकता के अनुसार लगातार बदलाव के लिए सक्षम बनाएं। यह उल्लेखनीय है कि जिस गति से आजकल विभिन्न तकनीकों में और विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं था। वही शिक्षा उपयोगी हो सकती है जो समय के साथ-साथ स्वयं को बदलने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाए।

अधिक उपयोगी और उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था तो वही होगी जहां शिक्षार्थी अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करें। केवल जानकारी को रटने के आधार पर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, किसी भी दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों का परीक्षाओं में पास होना किसी भी संस्था की गुणवत्ता का आकलन करने का पैमाना नहीं हो सकता। बोर्ड की परीक्षाओं में आधे से अधिक अंक तो प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के हो जाते हैं, जिनमें लगभग सभी को शत प्रतिशत अंक मिलते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा में यदि 10-20% भी अंक मिल जाएं तो वह छात्र उत्तीर्ण घोषित हो जाता है।

यदि 2047 तक विकसित भारत की कल्पना को साकार करना है तो अभी से हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली, विशेषकर मूल्यांकन की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। जहां तक केवल जानकारी हासिल करने का प्रश्न है, वह तो इंटरनेट के युग में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गूगल के माध्यम से कुछ सेकंड में प्राप्त कर सकता है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष ही माना जा सकता है कि जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने विदेशों में रहकर उच्च अध्ययन किया।

नई शिक्षा नीति में विषयों के चयन में लचीलापन लाने की बात कही गई है। साथ ही विद्यार्थी पूरे कोर्स में किसी समय प्रवेश लेकर छोड सकेगा। प्रश्न यही है कि क्या इसके लिए आवश्यक संख्या में उपयुक्त शिक्षक रखने हेतु पर्याप्त बजट बढ़ाया जाएगा?

कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ना तो देश के किसी काम की है न विद्यार्थियों के। देश में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति और कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। अब देश प्रतीक्षा कर रहा है, शिक्षा क्रांति की। इस क्रांति के बाद ही भारत के विकास में, शिक्षा अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकेगी।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ऑपरेशन सिंदूर : युद्ध विराम : व्यापारिक शीत युद्ध

रामनिवास बैरवा

इस्लाम को मानने वाली पुरूष जाति अपने लिए तो आधुनिकता और आधुनिक जीवन शैली चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शरियत को कठोरता से लागू करना जरूरी मानती है। इसीलिए जिन भी इस्लामिक देशों ने आधुनिक पूंजीवादी या समाजवादी जीवनशैली में महिलाओं को भी बराबर का भागीदार बनाया उन देशों के उदार शासकों को अमरीका जैसे पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों ने समानान्तर इस्लाम को कट्टरता से मानने वालों को उभारा और इस्लामी दुनिया को शरियत के दायरे में बांधे रखना चाहा, जैसे ईराक, ईरान, मिश्र, तुर्की आदि। तेल सम्पन्न मध्य पूर्व के देशों को इस्लामिक कट्टरता से बांधे रखा है। अन्य विकसित और विकासशील देशों को जहां इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या ज्यादा है, उन्हें आधुनिक औद्योगिक विकास के रास्ते से भटकाने के उद्देश्य से उन देशों में अस्थिरता बनाये रखना पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका का मुख्य लक्ष्य रहा है। नव-स्वतंत्र अविकसित औरा विकासशील देशों में अस्थिरता बनाये रखना और उन्हें आंतरिक संघर्षों या पड़ौसी देशों के साथ युद्धरत रखना भी एक उद्देश्य रहा है। इस प्रकार कट्टर इस्लामिक लोगों के द्वारा विभिन्न विकसित और विकासशील देशों में अपनी गतिविधियां करने से और कुछ हासिल हो या न हो, उग्र धार्मिक दक्षिणपंथी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं और उन देशों में उग्र-दक्षिणपंथी धार्मिक राष्ट्रवाद को सामने आने का मौका दिया गया।

इसी का परिणाम है कि पिछले दो दशकों में कई देशों में, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, भारत, कनाडा, इजराइल यहां तक कि स्वयं संयुक्त राज्य अमरीका में भी उग्र-दक्षिणपंथियों को उभरने का अवसर मिला- यह बात और है कि वे अपनी जीत की पूरी संभावना होने के बावजूद आम चुनावों में वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सके सिवाय संयुक्त राज्य अमरीका के, लेकिन, भारत में उग्र धार्मिक दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद हावी हो सके और सरकार भी बना सके।

इस प्रकार कट्टर हिन्दू राष्ट्रवाद, विदेशी इस्लामिक उग्रवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में सामान्य मुसलमानों को भी उग्र इस्लामी मानकर उनके प्रति दुर्भावनाएं पैदा करने में सफल रहे है। इन्हीं इस्लाम विरोधी भावनाओं का भारत के अन्य भागों में तो असर देखा ही गया लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य में, जहां मुसलमानों की संख्या बहुमत में है, वहां स्थानीय मुसलमान हिन्दू विरोधी नहीं है, क्योंकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है, जिसके लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक वहां आते हैं। इससे इनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है और वे हरेक पर्यटन-सीजन में उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक कश्मीर आयें, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और उनको शेष भारत के लोगों के साथ घुल-मिलकर रहने का अवसर मिले। ऐसी दशा में कश्मीर में हिन्दू मुसलमानों का भेद कोई मायने नहीं रखता। प्रसंगवश गत वर्ष, 2024 के पर्यटन सीजन में करीब अढाई करोड़ पर्यटक कश्मीर में आये थे। इस वर्ष उनकी संख्या चार करोड़ तक पहुंचने की सम्भावना थी। इसी सम्भावना को खतम करने के उद्देश्य से कट्टर इस्लामिक लोगों ने वहां सेनाओं को निशाना बनाने के बदले हिन्दू पर्यटकों को निशाना बनाया गया जिससे पर्यटकों की संख्या कम हों तथा कश्मीर के मुसलमानों दिमागों पर विपरीत असर पड़े।

पहलगाम में करीब दो हजार पर्यटक भारत के विभिन्न हिस्सों से आये हुए थे। बताते हैं कि उस दिन (22 अप्रैल 2025) वहां पर बैसरन में न तो पुलिस की व्यवस्था थी और न ही सुरक्षा बलों की तैनाती थी। लगभग चार उग्र इस्लामिक व्यक्ति अत्याधुनिक बंदूकों से लैस होकर वहां पहुंचे और करीब 20 पुरूष हिन्दू पर्यटकों को मार दिया। यह भी कहा जा रहा है कि उन उग्रवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों गोलियां मारी। संभव है कि उन व्यक्तियों के साथ में मौजूद स्त्रियों की मांगों में सिंदूर देखकर भी पुरुषों को मारा हो। उस दिन उस हत्याकांड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई या पुलिस और सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति को 'दी हिंदू' के दिनांक 22.04.2025 के ई-संस्करण में रात 9.29 बजे अपडेट किये गये समाचार तथा अन्य समाचारों में अगले दिन दिये गये समाचारों के अनुसार, केरल हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीश अपने परिवारों के साथ जम्मू-कश्मीर में अवकाश पर्यटन पर गये हुए थे तथा 21 अप्रेल को पहलगाम पहुंचे थे। लेकिन वे 22 अप्रेल को सुबह 9.30 बजे के लगभग पहलगाम से श्रीनगर के लिए निकल चुके थे। घटना के बाद समाचार मिलने पर न्यायिक जगत में चिंता फैल गयी। लेकिन वे न्यायाधीशगण और उनके परिवार सुरक्षित थे, न्यायिक क्षेत्रों में लोगों को सुकून देने वाली बात थी। आतंकवादियों के द्वारा किये गये उस हत्याकांड से पर्यटक हतप्रभ हो गये। कुछ स्थानीय मुसलमानों ने मृतकों और घायलों को लाने ले जाने में सहायता की। कई पर्यटकों को अपने घरों में शरण भी दी।

उस हादसे के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी होना लाजमी था। लेकिन सरकारें खासतौर से केंद्र सरकार के लिए उस हत्याकांड की उचित प्रतिक्रिया देना आवश्यक था। प्रधानमंत्री अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर आये लेकिन नौकरशाहों के साथ बैठक की और अगले दिन बिहार में आम चुनाव पूर्व की एक जनसभा में भाषण देने चले गये। इधर दो बार सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की। अन्ततः 7 मई, 2025 को सीमा पार पाकिस्तान में अवस्थित आतंकवादियों के केंद्रों पर ड्रोन से हमला किया। इस अभियान को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया। हमले की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या राजनीति थी, क्या लक्ष्य थे, वे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाये। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का एक गुपचुपा बयान जरूर सामने आया कि भारत आतंकी अड्डों पर ही हमला करेगा क्योंकि भारत की तरफ से 'ओपरेशन सिंदूर' कोई युद्ध की घोषणा नहीं थी। लेकिन, चौथे दिन शाम 5:30 में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। उसके काफी देर बाद भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने युद्ध विराम की घोषणा की। लगता है ट्रंप ने अपने शब्द भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रधानों के मुंह में डाले हों।

क्या, क्यूं, कैसे, सभी सेनाएं और भारत की जनता युद्ध-विराम की घोषणा से स्तंभित रह गये, लेकिन सरकार की न तो आलोचना कर सके और न ही सरकार से कुछ पूछ सके। उन चार दिनों के हवाई, मशीनी युद्ध से भारत ने और पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, इसका आंकलन और मूल्यांकन इतिहास में बाद में होगा। फिलहाल अमरीका का प्रत्यक्ष दखल उसके व्यापारिक हितों को ही परिलाक्षित करता है-निश्चित ही हमारे सबसे बड़े पड़ौसी चीन की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि युद्ध विराम के तत्काल बाद अमरीका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध को धीमा करने का उद्देश्य से टैरिफ में कमी करने की पहल की है। इससे जुड़ा एक अन्य मसला भी हो सकता है और वह है बलुचिस्तान का। जैसा कि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अपेक्षा थी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तेज हो कर लंबा चलेगा तो बलुचिस्तान को आजाद किया जा सकेगा। लेकिन, अमरीका नहीं चाहता कि बलुचिस्तान में शान्ति हो, क्योंकि बलुचिस्तान में खनिज संपदा बहुतायात से है वह अमरीका को किसी भी हालत में नहीं मिल पायेगी, चीन अपनी कोरीडोर की योजना के तहत उसे हांसिल करना चाहेगा पर वह उसे मिल नहीं पायेगी, अगर बलुचिस्तान अशांत बना रहता है। यह एक प्रकार से 'व्यापारिक शीत-युद्ध' है। इस मामले को बलुचिस्तान ने उजागर भी कर दिया है यह संदेश देकर कि भारत बलुचिस्तान को एक 'निर्वासित सरकार' की मान्यता दे, जैसे कि तिब्बत को 'निर्वासित सरकार' की मान्यता दे रखी है। लेकिन भारत सरकार अभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। बलुचिस्तान अपनी मुक्ति कस मार्ग खुद तय करे या भारत को गणतान्त्रिक संघ बन जाने पर उस संघ का सदस्य बने। क्योंकि आज के युग में किसी भी देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके उसे अपनी सीमाओं में मिलाना संभव नहीं है, इसके विपरीत देशों का विघटन होकर नये स्वतंत्र देश अवश्य बन सकते हैं।

कई लोगों का मानना है कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित परमाणु बमों के गोदाम के पास विस्फोट किये। परमाणु विकीरण और परमाणु बमों के नष्ट होने के खतरों को देखते हुए अमरीका ने युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन चाहे भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति सम्पन्न हों, वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले हजार बार सोचेंगे क्योंकि दोनों ही देशों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है और यह माना जा सकता है कि दोनों ही देशों में न तो नादिरशाह जैसा क्रूर कोई है जो दिल्ली जैसे शहर के लोगों की लाशों पर अट्टहास कर रहा हो, और न ही अमरीकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रमैन जैसा मानवता का दुश्मन कोई है जो अपने ही लोगों को वर्षों तक कष्ट भोगने के लिए परमाणु बम गिरा दे। बेशक, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सरकारों में उग्र धार्मिक राष्ट्रवादी बैठे हों, जो कि क्रूर भी हैं, निष्ठुर भी हैं और मानवता के प्रति असंवेदनशील भी हैं, फिर भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। जैसे पूंजीवादी साम्राज्यवादी अमरीका और उसके कट्टर विरोधी कम्युनिस्ट सोवियत संघ परमाणु हथियारों से सम्पन्न होते हुए भी उनका इस्तेमाल करने से 50 सालों तक क्या अभी तक भी बचते रहे है। और कभी गरम कभी नरम जैसा शीत युद्ध चलाते रहे। भारत और पाकिस्तान की जनता की रगों में वही पांच नदियों और गंगा-यमुना जैसी दो नदियों के पानी से बना खून बह रहा है वे अपने आपके दुश्मन नहीं हो सकते, चाहे उनकी सरकारें कितनी भी लड़ाइयां लड़ते रहें।

-रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

एक करोड़ की लागत से बने साइकिल ट्रैक की चार साल में हालत खस्ता

पॉलिटेक्निक कॉलेज के चारों ओर बने ट्रैक की हालत ऐसी हो गई है कि साइक्लिस्ट अब यहां साइकिल चलाने से भी कतराने लगे हैं

- **करीब चार साल पहले बीकानेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर नगर निकास न्यास ने लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर इस साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया था**
- **ट्रैक सार्दुलगंज सर्किल से शुरू होकर पॉलिटेक्निक रोड, नई शिवबाड़ी रोड, वर्धमान हॉस्पिटल के सामने होते हुए व्यास कॉलोनी के एंट्री पॉइंट तक जाता है**

बीकानेर, (निसं)। साइकिल प्रेमियों के लिए चार साल पहले जिस उम्मीद के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के चारों ओर नगर निकास न्यास ने साइकिल ट्रैक बनवाया था, वह अब पूरी तरह जमींदोज होता नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से बने इस ट्रैक की हालत ऐसी हो गई है कि साइक्लिस्ट अब यहां साइकिल चलाने से भी कतराने लगे हैं। खंभे, अतिक्रमण और टूटे अवरोधक इसे दुर्घटना का न्यौता बना चुके हैं। करीब 4 साल पहले बीकानेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर नगर निकास न्यास ने लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर इस साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया था। ट्रैक सार्दुल गंज सर्किल से शुरू होकर पॉलिटेक्निक रोड, नई शिवबाड़ी रोड, वर्धमान हॉस्पिटल के सामने होते हुए व्यास कॉलोनी के एंट्री पॉइंट तक जाता है और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के पास से होते हुए वापस सार्दुल गंज सर्किल पर आकर समाप्त होता है। शिवबाड़ी रोड पर साइकिल ट्रैक के पास बने अवरोधक कई जगह से टूट चुके हैं। रात के अंधेरे में यह अवरोधक दिखाई नहीं देते और यही कारण है कि कई बाइक व कार सवार यहां 2 फीट नीचे गिर चुके हैं। खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिवबाड़ी की ओर का हिस्सा, जहां सड़क स्तर नीचे है, बेहद खतरनाक हो चुका है।

साइक्लिस्ट भावना शर्मा ने कहा कि हर सुबह हम 15-20 लोग साइक्लिंग करते हैं, लेकिन ट्रैक की हालत देखकर डर लगता है। कई बार तो हमें बीच सड़क पर उतरना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। इतनी बड़ी सुविधा अगर इस हाल में छोड़ दी जाए, तो फिर खिलाड़ियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा। इस ट्रैक की चौड़ाई लगभग तीन मीटर है, लेकिन यह पूरी तरह उपयोग लायक नहीं है। ट्रैक के बीचों-बीच अभी तक विद्युत पोल खड़े हैं, जिनके हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों ने रास्ता और संकरा कर दिया है। कई जगहों पर आवारा पशु विचरण करते हैं, जिससे साइक्लिस्टों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है।

बीकानेर साइक्लिंग क्लब से जुड़े रोहित व्यास ने बताया, हमने कई बार प्रशासन से आग्रह किया कि ट्रैक की हालत सुधारी जाए। हाइवे पर साइक्लिंग करना बेहद खतरनाक है, लेकिन अब यही एकमात्र विकल्प बचा है। इतना पैसा खर्च कर जो सुविधा दी गई, उसकी देखरेख न होने से खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। सबसे पहले, ट्रैक के बीचों-बीच खंभे हटाने की कार्रवाई की जाए। डेयरी बूथ और अन्य अतिक्रमणों को हटाया जाए। टूटे हुए अवरोधकों को रिपेयर कर पुनः स्थापन किया जाए। रात के समय ट्रैक पर रिफलेक्टिव लाइट्स व बोर्ड लगाए जाए। ट्रैक की नियमित मॉनिटरिंग हो और हर 6 महीने में निरीक्षण अनिवार्य किया जाए। स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब के साथ समन्वय बनाकर साइक्लिस्टों की जरूरतें समझी जाये। बीकानेर को अगर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान दिलानी है तो ऐसी अधूरी और उपेक्षित योजनाओं पर पुनर्विचार जरूरी है। सिर्फ निर्माण कर देना पर्याप्त नहीं, उसकी देखरेख और रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सक्रियता दिखानी चाहिए, ताकि एक करोड़ की यह परियोजना फिर से बीकानेर के साइक्लिस्टों के लिए प्रेरणा बन सके।

राशिफल मंगलवार 27 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 2:51 तक, सुकर्मा योग रात्रि 10:54 तक, नाग करण प्रातः 8:32 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

कुमार योग प्रातः 8:32 से रात्रि 2:51 तक है। आज देव कार्य अमावस्या, भौमवती और भावुका अमावस्या, रोहिणी व्रत, सन्त ज्ञानेश्वरी जयन्ती है। आज करवीर व्रत, श्री गंगादशाश्व मेघ स्नान है। आज प्रतिपदा तिथि का क्षय हुआ है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:01 से 10:42 तक, लाभ अमृत 10:42 से 2:05 तक, शुभ 3:46 से 5:28 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:38, सूर्यास्त 7:09

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

धनु
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आर